



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

(ओ.आई. मामला सं. 06/2019)

विषय : चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/7/2019-डीजीटीआर.— मै. टेक्नोवा इमेंजिंग सिस्टम्स (प्रा) लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

2. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है, जिसे आम तौर पर डिजिटल प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। डिजिटल प्लेट्स का उपयोग मुद्रण उद्योग में डेटा को एक छवि (डॉट पैटर्न या पाठ) के रूप में कागज पर या गैर-शोषक सबस्ट्रेट जैसे टिन शीट या पॉली फिल्मों आदि पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, डिजिटल वर्कफ़्लो का उपयोग करते हुए मुद्रण प्रक्रिया में छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता वाले एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत, लेज़रों का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में छवि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

3. डिजिटल प्लेट्स को उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बनाया जाता है जिसे रासायनिक कोटिंग के साथ लेपित किया जाता है। डिजिटल प्लेट्स या तो पाजिटिव हो सकती हैं (गैर-एक्सपोज्ड एरिया फार्मर्स इमेज) या निगेटिव (एक्सपोज्ड एरिया फार्मर्स इमेज) हो सकती हैं। डिजिटल प्लेटों के प्रदर्शन को प्लेट विकास प्रक्रिया में रसायनों के कम उपयोग के साथ पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ सुधार भी किया जा सकता है, इसे डिजिटल ऑफसेट "रसायन मुक्त" / "ग्रीन प्लेट" के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरह, डिजिटल प्लेट्स के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है ताकि इसे प्रोसेसलेस प्लेट बनाया जा सके।

4. कोटिंग घटकों, जिन्हें 'सेंसिटाइज़र' के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए अलग-अलग होते हैं। कोटिंग घटकों और लेजर प्रकार के प्लेटसेटर्स के आधार पर, डिजिटल प्लेट्स को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों जैसे थर्मल, वायलेट और सीटीपीसीपी / यूवी सीटीपी (कंप्यूटर-टू-कन्वेंशनल प्लेट) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- i. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जो इन्फ्रा-रेड ऊर्जा का उपयोग करके एक्सपोज की जाती हैं, उन्हें थर्मल प्लेट्स कहा जाता है;
- ii. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जो दृश्य और निकट-दृश्य प्रकाश ऊर्जा (वायलेट लेजर) का उपयोग करके एक्सपोज की जाती हैं, उन्हें वायलेट प्लेट्स कहा जाता है; तथा
- iii. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स जो अल्ट्रा-वायलेट किरणों का उपयोग करके एक्सपोज की जाती हैं, उन्हें सीटीपीसीपी/ यूवी सीटीपी प्लेट्स के रूप में जाना जाता है।

5. सभी आयामों में सभी प्रकार के डिजिटल प्लेट्स विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। संबद्ध वस्तु अधिनियम के टैरिफ उप शीर्ष 8442.50 'के अंतर्गत आती है। हालांकि, अन्य शीर्षकों जैसे 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 और 7606.9290 जैसे अन्य शीर्षों के तहत संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद की पहचान के लिए उत्पाद का वर्णन लागू होगा।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित डिजिटल प्लेट्स अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन उन्हें "समान वस्तु" माना गया है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मेसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (प्रा.) लिमिटेड द्वारा पीयूसी के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया है कि पीओआई के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात विचाराधीन उत्पाद के उनके उत्पादन की तुलना में कम मात्रा में थे चूंकि भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन में याचिकाकर्ता के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर योग्यता को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग का गठन करता है।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

चीन जन. गण.

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसने सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमतों और शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज की एल्यूमीनियम की तुलना में कीमतों की तुलना यूरोपीय आयोग द्वारा चीन जन. गण. के बारे में बाजार विकृति अध्ययन; और भारतीय डीजीटीआर और अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पाटनरोधी जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य किसी प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश अर्थात् यूरोपीय संघ (बाद में इसे "ईयू" कहा जाएगा) कीमतों पर आधारित होगा। याचिकाकर्ता ने तुलनीय बाजार आकार और यूरोपीय संघ में कीमतों जो बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, के आधार पर यूरोपीय संघ को एक प्रतिनिधि देश के रूप में

प्रस्तावित किया है। याचिकाकर्ता ने पीयूसी के लिए यूरोपीय संघ के बाजार में अग्रणी उत्पादकों में से एक से बीजक प्राप्त किया और आवेदन के साथ उसे प्रदान किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्ताव किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम

11. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित के आधार पर जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है:

- i. कच्ची सामग्री: याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई लागत के आधार पर;
- ii. श्रम लागत: सार्वजनिक डोमेन में संबंधित देशों के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर;
- iii. बिजली की लागत: सार्वजनिक डोमेन में संबंधित देशों के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर। ताइवान और वियतनाम के लिए, भारत में बिजली की लागत को समान रूप में लिया गया है;
- iv. परिवर्तन लागत: याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई लागत के आधार पर;
- v. एसजीए लागत और वित्त लागत: याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई लागत के आधार पर; तथा
- vi. लाभ मार्जिन: सामान्य मूल्य को काम करने के लिए उचित लाभ मार्जिन माना जाता है।

12. प्राधिकारी जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर प्रथम दृष्टया विचार किया है और अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त समायोजन के साथ सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

निर्यात कीमत

13. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है। समुद्री भाड़ा, स्थानीय प्रभार, संभलाई प्रभार, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत और गैर-वापसी योग्य वैट (केवल चीन पीआर के मामले में) के आधार पर कीमत समायोजनों को दावा किया गया है। प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में ऐसे समायोजन पर अपनी सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार निर्यात कीमत पर समायोजन पर विचार किया है और डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर भी इसे लागू किया है।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

15. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन करने के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभ, नियोजित पूंजी पर नकद लाभ और आय के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

16. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच अवधि

17. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 (9 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल 2017 – मार्च, 2018 की अवधि और जाँच अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****भारत सरकार**

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

- i. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
- ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ सॉफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी

सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2019

(OI Case No. 06/2019)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam

F.No. 6/7/2019-DGTR.—M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd. (hereinafter also referred to as the ‘Petitioner’ or ‘Applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for imposition of anti-dumping duty on imports of Digital Offset Printing Plates (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or Product Under Consideration ‘PUC’) from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam, hereinafter referred to as subject countries.

Product under consideration (PUC)

2. The product under consideration in the present application is “Digital Offset Printing Plates”, also commonly referred to as “Digital Plates”. Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a ‘computer to the plate’ (CTp) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image.

3. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The performance of Digital Plates may also be improved with lesser use of chemicals in the plate development process

making it environment-friendly, also known as Digital Offset "chem-free"/ "green plates". Similarly, the performance of Digital Plates may also be improved to make it processless plates.

4. The coating components, also known as 'sensitizers', vary for different types of plates. Based on the coating components and laser type of platesetters, the Digital Plates may be broadly classified into three categories namely Thermal, Violet and CtCP/UV CtP ('Computer-to-Conventional Plate').

- i. Digital Offset Printing Plates that are exposed using infra-red energy are called Thermal plates;
- ii. Digital Offset Printing Plates that are exposed using visible and near-visible light energy (violet lasers) are called Violet plates; and
- iii. Digital Offset Printing Plates that are exposed using ultra-violet rays are known as CtCP/UV CtP plates.

5. All types of Digital Plates in all dimensions are covered within the scope of the product under consideration. The subject goods fall under Tariff Sub-heading '8442.50' of the Act. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 and 7606.9290 as well. Customs classifications are therefore indicative only and the product description would prevail for identifying the product.

Like Article

6. The Petitioner has submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the Petitioner. Digital Plates produced by the Petitioner and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Petitioner are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic industry and Standing

7. The application has been filed by M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd., as domestic industry of the PUC. The Petitioner has certified that the imports made by them during the POI were in small quantities as compared to their production of the product under consideration. Since the production of the Petitioner accounts for a major proportion in the total production of the PUC in India, the Petitioner satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

Countries Involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from China PR, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam.

Normal Value

China PR

9. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Petitioner has claimed that normal value should be constructed for China PR based on a comparison of London Metal Exchange prices and Shanghai Future Exchange prices of aluminium; market distortion studies regarding China PR by the European Commission; and treatment of China PR as a non-market economy in anti-dumping investigations conducted by the Indian DGTR and the US Department of Commerce.

10. Accordingly, the Petitioner has proposed that normal value for China PR be based on prevailing prices of the like article in a surrogate market economy country, i.e. the European Union (hereinafter referred to as "the EU"). The Petitioner has proposed the EU as a surrogate country based on the comparable market size and prices in the EU that are reflective of market economy principles. The Petitioner obtained invoices from one of the leading producers in the EU market for the PUC and has supplied the same with the application. The Petitioner has also proposed that normal value for China PR could be determined based on the cost of production in India.

Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam

11. The Petitioner has constructed normal values for Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam based on the following:
- Raw materials: based on the cost incurred by the Petitioner;
 - Labour cost: based on the information available for the respective countries in the public domain;
 - Electricity cost: based on the information available for the respective countries in the public domain. For Taiwan and Vietnam, the same has been taken as the electricity cost in India;
 - Conversion cost: based on the cost incurred by the Petitioner;
 - SGA cost and Finance Cost: based on the costs incurred by the Petitioner; and
 - Profit Margin: reasonable profit margin considered to work out the normal value.
12. The Authority, for the purpose of initiation, has prima facie considered the information made available by the petitioner regarding its cost of production and has constructed the normal value for all the subject countries with appropriate adjustments as per its consistent practice.

Export Price

13. The Petitioner has claimed the export price on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, local charges, handling charges, ocean insurance, inland freight, bank charges & credit cost, and non-refundable VAT (in case of China PR only). The Authority has considered adjustments on export price as per its consistent practice on such adjustments in earlier investigations and applied the same on DGCIS data.

Dumping Margin

14. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margins in respect of the subject goods from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury & Causal Link

15. Information furnished by the Petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and also in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Initiation of Anti-dumping Investigation

16. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

17. The period of investigation (hereinafter referred to as "POI") for the present investigation is from 1st July 2018 to 31st March 2019 (9 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Submission of information

18. The known exporters in the subject countries and their governments through their embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi-110001

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

Submission of information on confidential basis

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.

25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority